अवैध खनन पर नजर को चेक गेट तैयार

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: प्रदेश में अवैध खनन पर नजर रखने के लिए चेक गेट स्थापित करने की योजना इस वर्ष जून तक धरातल पर उतरने की संभावना है। इसके लिए खनन विभाग माईनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (एमडीटीएसएस) पर कार्य शुरू कर चुका है। विभाग का प्रयास जून तक चलने वाले खनन सत्र से पहले कम से कम हर जिले के कुछ प्रमुख स्थानों पर इसके जरिये निगरानी करने का है।

खनन विभाग प्रदेश को अधिक राजस्व देने वाले विभागों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग 900 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल किया था। इस वर्ष यह लक्ष्य 1100 करोड़ रुपये रखा गया है। खनन में राजस्व बढ़ोतरी के लिए अवैध खनन पर अंकुश लगाना जरूरी है। इस पर रोक विभाग के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। दरअसल, नदियों में खनन के

- देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर में लगने हैं 40 चेक गेट
- जून से इन चेक गेट को सक्रिय करने के लिए चल रही तैयारी, बनाए जा रहे कमांड सेंटर

लिए निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर बड़े पैमाने पर बेतरतीब ढंग से खनन, एक ही रवन्ने से कई-कई फेरे, उपखनिज का दुलान जैसी शिकायतें आम हैं। इससे जहां सरकार को राजस्व की हानि होती है, वहीं नदियों में अवैज्ञानिक ढंग से हुआ अवैध खनन बाढ़ के खतरे को भी बढ़ाता है। इसे देखते हुए खनन विभाग ने अवैध खनन व ओवर लोडिंग पर नजर रखने के लिए एमडीटीएसएस योजना बनाई है। इस योजना के लिए गत वर्ष शासन ने 93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इस धनराशि से देहरादून में आठ चेक गेट, हरिद्वार में 13 चेक गेट, नैनीताल में 10 चेक गेट और ऊधम सिंह नगर में नौ चेक गेट लगाए जाने हैं। इन गेट पर खनन पर नजर रखने के लिए एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, राडार व फ्लड लाइट भी लगाई जाएगी। इससे इस गेट से होकर गुजरने वाले वाहनों के संबंध में पूरी जानकारी आनलाइन मिल सकेगी। इसके लिए इन चारों जिलों के ज़िला मुख्यालय में मिनी कमांड सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

निदेशक खनन राजपाल लेघा ने बताया कि चेक पोस्ट लगाने का कार्य कई स्थानों पर लगभग पूरा हो चुका है। विभाग का प्रयास प्रमुख स्थानों पर जून तक इन चेक पोस्ट को सक्रिय करने का है।